यूपी की शुगर मिलों पर एरियर का बढ़ा खतरा

भारी पड़ सकता है किसानों को गन्ना पेमेंट की किस्तें चुकाना

[श्रेया जय | नई दिल्ली]

उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री पर पैदा हुआ शटडाउन का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए एक और क्राइसिस पैदा होती दिखाई दे रही है।

गन्ने की कीमतों में किसी बदलाव के न होने से इंडस्ट्री को लग रहा है कि इसके 280 रुपए प्रति क्विंटल के भाव के साथ गन्ने के एरियर अगले साल भारी-भरकम लेवल पर पहुंच सकते हैं। शुगर मिलों को डर सता रहा है कि उनके लिए इसकी किस्तें तक चुकाना नामुमकिन साबित हो सकता है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा के मुताबिक, 'अगर शुगर प्राइस मौजूदा लेवल पर ही बने रहते हैं और आने वाले महीनों में इनमें कोई गिरावट नहीं आती है तो यूपी की मिलें खरीदे गए गन्ने के लिए 20 से 30 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तक देने के लायक नहीं रहेंगी।' राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच रविवार को गन्ने की कीमत चुकाने पर एक समझौता हो गया था।

इस एग्रीमेंट के तहत मिलें दो किस्तों में गन्ने के लिए 280 रुपए प्रति क्विंटल का दाम देने को राजी हुई थीं। इसमें पहली किस्त में मिलें गन्ने की खरीद के वक्त 260 रुपए का दाम देंगी और बकाया 20 रुपए प्रति क्विंटल का दाम बाद में देंगी। यूपी में मौजूदा वक्त में शुगर का दाम 29 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है जो पिछले साल इसी वक्त करीब 34 रुपए प्रति क्विंटल था।

अबिनाश वर्मा ने कहा, 'पिछले साल के कैरी-फॉरवर्ड को भी अगर शामिल कर लिया जाए, तो गन्ने का बकाया अगले साल तक करीब 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। मिलों के लिए इसे मैनेज करना काफी मुश्किल होगा।'

यूपी की सबसे बड़ी शुगर मिलों में से एक के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि उन्होंने समझौता इसलिए किया है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अधिकारी ने कहा, 'अब कम से कम बैंक तो हमें वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए राजी हैं।' इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा वर्मा ने कहा, 'राज्य सरकार का यह एलान कि वे 3 महीने में लॉन्ग टर्म रेशनलाइज्ड केन प्राइस को देखेंगे, इससे बैंकों में कुछ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि गन्ने की प्राइसिंग के लिए जल्द ही कोई फॉर्मूला तय हो सकता है।'

> **"अगर शुगर प्राइस मौजूदा लेवल पर ही बना रहता है और आने वाले महीनों में इसमें कोई गिरावट नहीं आती है तो यूपी की मिलें खरीदे गए गन्ने के लिए 20 से 30 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तक देने के लायक नहीं रहेंगी**
>
> **अबिनाश वर्मा,** डायरेक्टर जनरल, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर कोई गेन प्राइसिंग फॉर्मूला लेकर नहीं आती है, तो अगले सीजन तक चीजें काफी खराब हो जाएंगी। प्रदेश की मिलों की तब बिजनेस नुकसान में जाने से मिलें बंद करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में गन्ने का बकाया करीब 2,400 करोड़ रुपए का है। राज्य की शुगर इंडस्ट्री ने ऊंचे प्राइस को देखते हुए मिलों को बंद रखने का फैसला किया था। राज्य सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद मिलों ने गन्ने की पेराई फिर से शुरू करने का एलान किया है।

The Economic Times. (Hindi)
5-12-13.